

<><><><><><><>

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज "प्रधानमंत्री किसान संपदायोजना" के लिए एक हजार नौ सौ बीस करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल छ हजार पांच सौ बीस करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी।
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में ई डी की छापेमारी। आर्थिक अपराध शाखा का प्राथमिकी के आधार पर कई लोगों के खिलाफ मामले की जांच शुरू हुई।
- कृषि विभाग ने आधिकारिक तौर पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में स्पाइस प्रवाह का नामक एक अग्रणी अभियान का शुभारंभ किया।
- निकोबार ज़िले के उपायुक्त ने कार निकोबार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रदर्शन स्थलों का क्षेत्रीय भ्रमण किया।

<><><><><><>

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पन्द्रहवें वित्त आयोग चक्र दो हजार इक्कीस-बाईस से दो हजार पच्चीस-छब्बीस के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" के लिए एक हजार नौ सौ बीस करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल छ हजार पांच सौ बीस करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दो हजार पच्चीस-छब्बीस से दो हजार अटठाईस-उनतीस तक चार वर्षों की अवधि के लिए दो हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को भी आज स्वीकृति दे दी है। इसमें वित्त वर्ष दो हजार पच्चीस-छब्बीस से प्रत्येक वर्ष पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। वित्त वर्ष दो हजार पच्चीस-छब्बीस से वित्त वर्ष दो हजार अटठाईस-उनतीस तक दो हजार करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के आधार पर, एन.सी.डी.सी चार वर्षों की अवधि में खुले बाजार से बीस हजार करोड़ रुपये जुटा सकेगा। एन.सी.डी.सी इस धन राशि का उपयोग सहकारी समितियों को नई परियोजनाएं स्थापित करने/संयंत्रों के विस्तार हेतु ऋण देने और कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगा।

<><><><><><>

प्रवर्तन निदेशालय ने अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक में कथित धोखाधड़ी के संबंध में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में पहली बार छापेमारी की है। पोर्ट ब्लेयर में दो स्थानों और कोलकाता में नौ स्थानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान, एजेंसी ने विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बरामद किए। इससे बैंक द्वारा ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का पता चला है। निदेशालय ने अंडमान निकोबार पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी के आधार पर कई लोगों और बैंक के अधिकारियों के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है।

<><><><><><>

कृषि विभाग, लिटिल अंडमान क्षेत्र ने आज मसाला प्रवाह पहल के अंतर्गत एक बड़े पैमाने पर रोपण कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य मसाला खेती का विस्तार करना था। इस कार्यक्रम में किसानों, पंचायती राज संरथाओं और क्षेत्रीय पदाधिकारियों की भागीदारी देखी गई। उद्घाटन समारोह सुबह दस बजे रामकृष्णपुर ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग पच्चीस किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन परमनाथन, प्रमुख, पंचायत समिति, लिटिल अंडमान द्वारा रामकृष्णपुर की प्रधान सिउली मंडल और हटबे के प्रधान रुद्रमूर्ति सहित पंचायत समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्र में मसालों की सतत खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कृषि अधिकारी मैरी मैगडलीन ने किसानों का स्वागत किया और द्वीप भर में मसालों की खेती को बढ़ावा देने में इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने रथायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में मसाला प्रवाह कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विचार व्यक्त किए। कृषि सहायक दिनेश चंद्र दास ने मसालों की खेती पर तकनीकी जानकारी प्रदान की, जिसमें काली मिर्च की किस्में और लिटिल अंडमान में उगाए जाने वाले मसालों की निर्यात क्षमता शामिल थी। चार चिह्नित लाभार्थी किसानों अशोक बछार, श्यामलाल मंडल, कमलेश मंडल और नोनी गोपाल बरोई की एक हेक्टेयर भूमि पर दो सौ काली मिर्च की कलमें लगाई गईं। किसानों को दो सौ पौधे वितरित किए गए।

<><><><><><>

अंडमान और निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग ने आधिकारिक तौर पर स्पाइस प्रवाह नामक एक अग्रणी अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य एकीकृत खेती और संवर्धन द्वारा मसाला संवर्धन – लचीली सुगंधित मूल्य श्रृंखलाओं और समग्र खेती को बढ़ावा देना है जो कि इसके नाम को भी सार्थक करता है। इस अभियान का उद्घाटन इकतीस जुलाई को मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने सिप्पीघाट स्थित जैविक बागवानी फार्म में वृक्षारोपण कार्यक्रम से किया। मुख्य अतिथि के साथ अन्य अधिकारी चंचल यादव, डॉ. सचिन शिंदे, अर्जुन शर्मा, पल्लवी सरकार, ज्योति कुमारी शामिल रहे। कृषि निदेशक, प्रियंका कुमारी ने मुख्य अतिथि का स्पाइस प्रवाह पहल के लिए उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। पल्लवी सरकार, सचिव (कृषि) ने स्पाइस प्रवाह पहल के बारे में जानकारी दी और इसके उद्देश्यों, कार्यान्वयन रणनीति और द्वीपों में मसाला खेती और किसानों की आजीविका पर इसके अपेक्षित प्रभाव पर प्रकाश डाला। सचिव (कृषि) ने बताया कि “सुगंध वृक्षों की प्रवाह— मसाला खेती के माध्यम से उन्नति” की प्रभावशाली टैगलाइन के साथ, इस पहल का उद्देश्य दालचीनी, जायफल और काली मिर्च जैसे वृक्ष—आधारित मसालों की स्थायी खेती, मूल्य संवर्धन और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देना है। सिप्पीघाट के साथ—साथ मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत में उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई किसान शामिल हुए। मीठाखाड़ी के ग्राम प्रधान मोहम्मद शफीक ने आकाशवाणी श्री विजयपुरम से कहा कि वह मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे।

<><><><><><><>

निकोबार ज़िले के उपायुक्त अमित काले मारुति राव ने कार निकोबार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रदर्शन स्थलों का क्षेत्रीय भ्रमण किया। तामालू गाँव में आदिवासी किसान लेस्ली ने उन्नत फसल किस्मों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और मुर्गी पालन के बारे में बताया। उपायुक्त ने किसानों की नई पद्धतियों को अपनाने की इच्छा और खेत पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने में के.वी.के की भूमिका की सराहना की। उपायुक्त ने बिंग लापती गाँव का दौरा किया जहाँ उन्होंने आदिवासी किसानों एस्टर रेजिनल और पैट्रिक जान मोहम्मद से जानकारी ली। इन किसानों ने फसल प्रदर्शन, मृदा स्वारक्ष्य प्रबंधन और सब्जी की खेती के अपने अनुभव साझा किए। उपायुक्त ने के.वी.के की पहलों से उत्पादकता और आजीविका की स्थिरता में हुए ठोस सुधारों की सराहना की। उन्होंने निकोबार में समग्र ग्रामीण विकास और जनजातीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और के.वी.के के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इस यात्रा का समन्वय और संचालन डॉ. ई. बी. चाकुरकर, निदेशक, आई.सी.ए.आर—सी.आई.ए.आर.आई, श्री विजय पुरम द्वारा किया गया और इसका नेतृत्व डॉ. संतोष कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख, आई.सी.ए.आर—के.वी.के, निकोबार ने किया।

<><><><><><><>